

डोभाल की खरी-खरी

कारंगिल विजय दिवस से ठीक पहले जोहानिसर्बग में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के विदेश मासलों के आयोग के निदेशक वांग यी से राष्ट्रीय सुक्ष्मा सलाहकार अजीत डोभाल ने जिस बेलाग तरीके से भारत के भरोसा दरकने की बात कर्नी, उसके गहरे अर्थ हैं। खासकर तब, जब साल 2019 के बाद सीमा संबंधी मसलों पर दोनों देशों के विशेष प्रतिनिधियों की यह पहली बैठक हो। गौरतलब है, मई 2020 में जिस समय गलवान की घटना घटी थी, वांग यी चीन के विदेश मंत्री हुआ करते थे, और इस वक्त वह न सिफ्फ वहाँ के शक्तिशाली पोलिट ब्यूरो के सदस्य हैं, बल्कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग के करीबी भी माने जाते हैं। इसलिए डोभाल की इस दोटूक बात से बीजिंग को एहसास हो गया होगा कि सरहद पर तनाव पैदा करके वह नई दिल्ली को सैदेबाजी के लिए बाध्य नहीं कर सकता! डोभाल से पूर्व भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर भी अनेक मौकों पर स्पष्ट कर चुके हैं कि जब तक सीमा पर शार्टपूर्ण संबंध न होंगे, तब तक दूसरी तमाम बातें मायने नहीं रखतीं। चीन हमेशा से यही चाहता रहा है कि सीमा संबंधी मसले को पीछे रखकर बाकी विषयों पर, खासकर कारोबारी रिश्तों के विस्तारीकरण की दिशा में आगे बढ़ा जाए, मगर भारत के सख्त रुख का ही नतीजा है कि उसके रवैये में कुछ नरमी दिखी है। मगर यह कितनी वास्तविक है, इसकी परख उसके द्वारा उठाए जाने वाले कदमों से होगी। क्या वह वास्तविक नियंत्रण रेखा पर मई 2020 से पहले की स्थिति कबूलने को तैयार है? दरअसल, कोविड महामारी के समय से ही चीनी अर्थव्यवस्था गंभीर मुश्किलों का सामना कर रही है। अब यह राज की बात नहीं कि अमेरिकी तनातनी के कारण उसके यहाँ से निवेशकों का पलायन हुआ है और कई चीनी कंपनियों को पश्चीमी देशों में तरह-तरह के प्रतिबंधों से गुजरना पड़ रहा है। अभी-अभी भारत सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन बनाने वाली उसकी एक कंपनी के 8,200 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव को दुकराया है। खबर यह भी है कि घरेलू मांग में कमजोरी के कारण चीन की अर्थव्यवस्था के सामने नए किस्म का संकट पैदा हो गया है और पोलिट ब्यूरो ने इससे निपटने वाले आंतरिक स्तर पर मांग को मजबूती देने के लिए नीतिगत प्रोत्साहन का रास्ता सुझाया है। भारत की मजबूत होती अर्थात् स्थिति व वैश्विक मंचों पर उसके बढ़ते महत्व को स्वीकारने में बीजिंग को चाहे जितनी हिचक हो, वह इस असलियत की अनदेखी नहीं कर सकता। इसलिए वह चाह रहा है कि द्विपक्षीय रिश्तों में जमी बर्फ को पिघलाने का रास्ता निकाला जाए। भारत तो हमेशा से ही पड़ोसी देशों से बेहतर संबंधों का हिमायती रहा है, मगर चीन और पाकिस्तान से उसे बार-बार निराशा ही हाथ लगी है। यह सही है कि भूगोल पड़ोसी चुनने की इजाजत नहीं देता, मगर ताल्लुकात साफ नीयत पर ही टिकते हैं। शी जिनपिंग यदि वाकई विश्वास-बहाली को लेकर गंभीर हैं, तो बीजिंग को खुले दिल व ठोस कार्यक्रमों के जरिये सीमा-विवाद सुलझाने की पहल करनी चाहिए।

लोकतंत्र पर हमला

इस्ताइशना संसद न समरपार का पहले राजनवेलनस बिल पास कर दिया, जिसे कथित न्यायिक सुधार का पहला चरण बताया जा रहा है। यह बिल नेतृत्वाधू सरकार की जुडिशरी को कमज़ोर करने की विस्तृत योजना का हिस्सा है और इसके खिलाफ वहाँ पिछले करीब छह महीने से व्यापक प्रदर्शन हो रहे हैं। संसद में बिल पास किए जाते समय विषय विपक्ष मौजूद नहीं था, इसीलिए 64-0 से पास हो गया। लेकिन संसद के बाहर सड़कों पर उस समय भी हजारों लोग प्रदर्शन कर रहे थे। हालांकि नेतृत्वाधू सरकार इस बिल को जुडिशरी पर हमला नहीं मानती। उसके मुताबिक, यह देश के अंदर सत्ता समीकरण को फिर से संतुलित करने की कोशिश है। लेकिन इसमें दो राय नहीं कि पावर इक्वेशन को रीबैलेंस करने के नाम पर सरकार ने जुडिशरी के अधिकार कम किए हैं। इस बिल के कानून बनने के बाद न्यायपालिका को सरकार के फैसलों की समीक्षा करने के उन्हें अवैध घोषित करने का अधिकार नहीं रह जाएगा। जाहिर तौर पर यह एक निवाचित सरकार द्वारा देश के लोकतंत्र को कमज़ोर करने का ऐसा मामला है, जिसे दुनिया के तमाम लोकतांत्रिक देशों और समाजों के लिए चेतावनी के रूप में लिया जाना चाहिए। किसी जमाने में वामपंथी विचारधारा को लोकतंत्र के लिए एक खतरे के रूप में देखा जाता था। लेकिन आज दुनिया के कई देशों में दक्षिणपंथ की तेजी से उभरती प्रवृत्तियां लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए खतरा बनती दिख रही हैं। ऐसे में इसे हलके में नहीं लिया जा सकता। यही वजह है कि इस्ताइल के सबसे करीबी देशों में गिरे जाने वाले अमेरिका ने भी उसे ऐसे विधेयकों पर जल्दबाजी न करने और आम सहमति बनाने का सुझाव दिया था। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन, नेतृत्वाधू को भेजे संदेश में यहाँ तक कह चुके हैं कि इन बिलों को पारित करने पर जोर देकर उनकी सरकार दोनों देशों के रिश्ते को दांव पर लगा रही है। लेकिन खुद भी ब्राह्मचार के आरोपों से घिरे नेतृत्वाधू ने सभी सुझावों को दरकिनार करते हुए जुडिशरी के पर करने का अपना अर्जेंडा लागू करना शुरू कर दिया है। ऐसे में अब पहले तो यह देखना होगा कि इस्ताइल में इसके किस तरह के नतीजे सामने आते हैं। इसे जहाँ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कही जा रही है वहीं इसके खिलाफ व्यापक हड़ताल की भी चेतावनी दी जा रही है।

Social Media Corner

आप में से जो लोग शोध में रुचि रखते हैं, उन्हें उच्चतर शोध पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। मरीज के लिए दवा प्रीसक्राइब करना जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण नई औषधियां विकसित करना है। मुझे उम्मीद है कि यदि आप शोध जारी रखेंगे तो आप चिकित्सा विज्ञान में नई दिशाओं की खोज कर पाएंगे। आप नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त कर सकते हैं। (राष्ट्रपति द्वापटी मर्म के टिवटर अकाउंट से)

कारगिल विजय दिवस भारत के उन अद्भुत पराक्रमियों की शौर्यगाथा को सामने लाता है, जो देशवासियों के लिए सदैव प्रेरणाशक्ति बने रहेंगे। इस विशेष दिवस पर मैं उनका हृदय से नमन और

पदन करता हूं जय हॉ !
(प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के टिवटर अकाउंट से)

अदम्य साहस, शौर्य और वीरता के प्रतीक
कारणिल विजय दिवस के अवसर पर देश के
अमर वीर जवानों की शहादत को शत-शत नमन ।

(जीए टेक्स्ट सोलो के टिवटर अकाउंट से)

विकराल समर्थ्या बनता लघुर शहरी ढांचा

ANALYSIS

तरुण गुप्त

लचर बुनियादी ढांचे और जर्जर स्थानीय निकायों की समस्या बहुत विकराल हो चुकी है। इनकी निदा को लेकर एक प्रकार के रूप में हमारे समक्ष एक चुनौती यह भी उत्पन्न हो गई है कि ऐसी आलोचना की अधिवृत्ति में नयापन कैसे लाएं। इस साल भी मानसून को लेकर हमारा अनुभव पिछले वर्ष से अलग नहीं रहा। हमारे शहरों की भयावह स्थिति और मानसून से निपटने की प्रशासन की तैयारी ने समान रूप से निराश किया। नियंत्रण का ने लगाई जाने वाली अतीत से कोई सीख या सबक लिया ही नहीं जा रहा। इसके कारण हमारे शहर जरा सी बारिश में पानी से लबालब हो जाते हैं तभी उनमें जलजमाव, ट्रैफिक जाम, सड़कों का धंस जाना, करंट दौड़ाना जाने से लेकर जानमाल की भाँति क्षति होती है। विडंबना यह है विद्युत ऐसी घटनाएं इतनी आम हो गई हैं कि ये हमें आक्रोशित अवश्यक करती हैं, किंतु आश्वार्यचिकि नहीं। लचर बुनियादी ढांचे और जर्जर स्थानीय निकायों की समस्या

अपने स्पष्टीकरण में प्रशासन ने अप्रत्याशित एवं एकमुश्त वर्षा जैसे कारण गिनाए। इन बहानों से अवश्य ही बाज आना चाहिए। अप्रत्याशित शब्द तो इतने अतिशय रूप से उपयोग होने लगा है कि अपना अर्थ खोता जा रहा है। हर साल रिकार्ड टूट रहे हैं। इसे व्यापक अराजकता के बचाव से अधिक सांख्यिकीय आंकड़ेबाजी के रूप में देखना चाहिए। जहां तक एकमुश्त बारिश की बात है तो यह निष्कर्ष निकालने के लिए आपको कोई जलवायु विशेषज्ञ होने की आवश्यकता नहीं कि वैश्विक तापवृद्धि के कारण समय के साथ प्रतिकूल मौसमी परिघटनाओं की आवृत्ति बढ़ती जा रही है। पूरी दुनिया में लोग इससे भलीभांति परिचित हैं कि उन्हें भीषण ठंड, झुलसाने वाली गर्मी और अतिवृष्टि जैसी स्थितियों के लिए स्वयं को तैयार रखना होगा। सवाल यही है कि हमारी जिम्मेदार संस्थाएं इसके लिए किनीं तैयार हैं? आखिर भारतीय शहर कुछ ही घटों की बारिश में क्यों अव्यवस्था से कराहने लगते हैं?

A photograph showing a severe traffic jam on a flooded city street. The water covers the entire width of the road, with vehicles like cars, SUVs, and a blue bus partially submerged. A person wearing a red shirt and a black helmet is riding a motorcycle through the water on the right side of the frame. The license plate of the white car in front is visible as HR 46E 2114.

आवृत्ति बढ़ती जा रही है। पूरी दुनिया में लोग इससे भलीभांति परिचित हैं कि उन्हें धीरण ठंड, झुलसाने वाली गर्मी और अतिवृष्टि जैसी स्थितियों के लिए स्वयं को तैयार रखना होगा। सबाल यही है कि हमारी जिम्मेदार संस्थाएं इसके लिए कितनी तैयार हैं? आखिर भारतीय शहर कुछ ही घंटों की बारिश में क्यों अव्यवस्था से कराहने लगते हैं? इसकी पड़ताल करें तो पाएंगे कि कालबाह्य ड्रेनेज के साथ ही अपर्याप्त सीवेज नेटवर्क इसका सबसे प्रमुख कारण है। अधिकांश शहरों में बरसाती नाले-नालियां सैकड़ों वर्ष पुरानी हैं। इन्हें अंग्रेजों ने तब बनाया था, जब आबादी मौजूदा स्तर से बहुत कम थी। इससे भी बदतर है इन नालियों में बहने वाली सामग्री। इनमें केवल वर्षा का पानी ही नहीं, बल्कि अशोधित सीवेज, हर किस्म का कचरा और औद्योगिक अपशिष्ट भी बहता है। अधिकांश भारतीय शहरों के आधे से भी कम हिस्से में सीवेज कवरेज है। आधे से अधिक घर सीवेज शोधन संयंत्रों से नहीं जुड़े हैं। शहरों के एक बड़े हिस्से में सीवेज लाइन नहीं हैं। कारखानों से निकलने वाले अपशिष्ट के शोधन में लगे संयंत्र स्तरीय नहीं हैं। इस अशोधित सीवेज और औद्योगिक अपशिष्ट को नालियों (या ड्रेन्स) में बहा दिया जाता है, जिस कारण ये अट जाती हैं और फिर जरा सी बारिश में अनियन्त्रित होकर बहने लगती हैं। हमारा लक्ष्य रहा है कि इन नालियों को सीधे हमारी पवित्र नदियों में गिरने से पहले शोधन संयंत्रों के साथ जोड़ दिया जाए। जहां यह कार्य अभी भी अपूर्ण है, वहाँ हमें यह भी विचार करना चाहिए कि क्या यह प्रयास अपने आप में पर्याप्त है? क्या हम यह स्वीकार कर सकते हैं कि कचरे से भरी नालियां हमारे शहरों में कई किलोमीटर लंबा विस्तार लेकर बहती रहें? वे पर्यावरण को प्रदूषित करती हैं, भूजल को दूषित करती हैं और खेती को हानिकारक बनाती हैं। नियमित अंतराल पर दुर्घटनाओं के कारण इनमें गिरने से लोगों को जान भी गंवानी पड़ती है। इन परिस्थितियों में खुले में शौच से मुक्ति का हमारा दावा भी बेमानी लगता है। इसका समाधान खासा सरल, लेकिन स्पष्ट रूप से गायब है। आखिर प्रत्येक घर और प्रतिष्ठान में एक भूमिगत पाइप कनेक्शन सुनिश्चित कर उसे शोधन संयंत्र के साथ जोड़ना कितना कठिन है? केवल शोधित सीवेज ही नालियों में बहे। इन नालियों को ढक दिया जाए ताकि वे किसी बड़े कूड़ेदान की मानिन्द बनकर न रह जाएं। इन नालियों को ढकने से इनके ऊपर बनने वाले ढांचे का विभिन्न उत्पादक रूपों में उपयोग कर लाभ भी उठाया जा सकता है। अपने नागरिकों को स्वास्थ्य के अनुकूल जीवन स्थितियां उपलब्ध कराने के लिए विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था संसाधनों की कमी का बहाना नहीं बना सकती। हमें ड्रेनेज नेटवर्क का विस्तार करने के साथ ही उसे अतिक्रमण से मुक्त रखने की आवश्यकता है। हम पर्याप्त वर्षा जल संरक्षण के लक्ष्य से भी अभी काफी दूर हैं। इससे न केवल जलभराव से बचाव में मदद मिलेगी, बल्कि अतिरिक्त पानी इकट्ठा होकर भूजल स्तर को बढ़ाने में भी सहायक होगा। प्रबंधन का एक आधारभूत सिद्धांत है-यूनिटी आफ कमांड यानी एकीकृत कमान, जिसका पालन नहीं किया जाता। ड्रेनेज और सीवेज नेटवर्क का संचालन एवं रखरखाव विभिन्न विभागों एवं मंत्रालयों के बीच फैला है। नगर निगम, विकास प्राधिकरण, सिंचाव विभाग, जल विभाग और कैटोनमेंट बोर्ड आदि की अपनी भूमिका होती है। विडंबना यही है कि जिम्मेदारी सभी की है, किंतु जवाबदेही किसी की नहीं। ऐसे में इन संबंधित संगठनों के बीच एक अनुक्रम स्थापित कर उन्हें उससे अनुरूप जवाबदेह बनाना उपयोगी एवं प्रभावी सिद्ध होगा। स्मार्ट सिटी की तो बात रहने ही दीजिए, हमें रहने योग्य शहर मिल जाएं तो वहाँ काफी है। शहरों को रहने योग्य बनाने की राह में अनेक बारी कठिनाइयों से निपटने के लिए हमें सीधे और ड्रेनेज का प्रभावी उपाय करना ही होगा। यह स्पष्ट है कि हमारे देश में नागरिक सुविधाओं की गुणवत्ता हमारी अर्थिक प्रगति के अनुपात में हम स्वच्छता के मानकों पर अपनी क्षमताओं से बहुत पीछे हैं। ऐसे में, नागरिकों से मैं यही कहना चाहूँगा कि इन नारकीय परिस्थितियों को बदाश्त करने हमारी मजबूरी हो सकती है।

मणिपुर संघर्ष में ओरते क्यों बनीं निशाना

गया। लोकन ससद के बाहर सड़कों पर उस समय भा हजारा लागू प्रदर्शन कर रहे थे। हालांकि नेतन्याहू सरकार इस बिल को जुड़ीशी पर हमला नहीं मानती। उसके मुताबिक, यह देश के अंदर सत्ता समीकरण को फिर से संतुलित करने की कोशिश है। लेकिन इसमें दो राय नहीं कि पावर इक्वेशन को रीबैलेस करने के नाम पर सरकार ने जुड़ीशी के अधिकार कम किए हैं। इस बिल के कानून बनने के बाद न्यायपालिका को सरकार के फैसलों की समीक्षा कर-के उन्हें अवैध घोषित करने का अधिकार नहीं रह जाएगा। जाहिर तौर पर यह एक निर्वाचित सरकार द्वारा देश के लोकतंत्र को कमज़ोर करने का ऐसा मामला है, जिसे दुनिया के तमाम लोकतांत्रिक देशों और समाजों के लिए चेतावनी के रूप में लिया जाना चाहिए। किसी जमाने में वामपंथी विचारधारा को लोकतंत्र के लिए एक खतरे के रूप में देखा जाता था। लेकिन आज दुनिया के कई देशों में दक्षिणपंथ की तेजी से उभरती प्रवृत्तियां लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए खतरा बनती दिख रही हैं। ऐसे में इसे हलके में नहीं लिया जा सकता। यही वजह है कि इस्लाइल के सबसे करीबी देशों में गिने जाने वाले अमेरिका ने भी उसे ऐसे विधेयकों पर जल्दबाजी न करने और आम सहमति बनाने का सुझाव दिया था। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन, नेतन्याहू को भेजे सदैश में यहां तक कह चुके हैं कि इन बिलों को पारित करने पर जोर देकर उनकी सरकार दोनों देशों के रिश्ते को दांव पर लगा रही है। लेकिन खुद भी भ्रष्टचार के आरोपों से घिरे नेतन्याहू ने सभी सुझावों को दरकिनार करते हुए जुड़ीशी के पर करतरने का अपना अजेंडा लागू करना शुरू कर दिया है। ऐसे में अब पहले तो यह देखना होगा कि इस्लाइल में इसके किस तरह के नतीजे सामने आते हैं। इसे जहां सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कही जा रही है वहीं इसके खिलाफ व्यापक हड़ताल की भी चेतावनी दी जा रही है।

जाल म फसा हुआ ह, जा उनका
अस्मिता और सम्मान के नाम पर
उन्हें समाज के हर टकराव में
घसीट कर उनकी देह को रणक्षेत्र
बना देता है। स्त्री की अस्मिता
को उसके शरीर तक सीमित कर
देने की बेहूदी सोच युगों-युगों से
चली आ रही है। द्वापर युग की
मिथकीय द्रौपदी को निर्वस्त्र करने
की जो हरकत कौरवों की
राजसभा से शुरू हुई थी, वह
आज तक जारी है। मणिपुर में भी
हाल के दिनों में यही देखने को
मिला। आलम यह है कि मामला
पुरुषों के बीच का हो, दो जातियों
या उप-जातियों के बीच का या
धार्मिक समूहों या मात्र दो घरों के
बीच का। टकराव में प्रतिद्वंद्वी को
हराने मात्र से विजय पूरी नहीं
होती। विरोधी पक्ष के कितने ही
खजाने आप लूट लें, कितने ही
समर्थक कब्जे में कर लें,
प्रतिद्वंद्वी की स्त्रियों की देह न
लूटी तो सब बेकार, ऐसा
मर्दवादी सिद्धांत आमतौर पर
चलता है।
राजशाही भी जहां खत्म हुई, वहां

बहुत कुछ बदला, लोकन उसक
अनुरूप मर्दवादी या
पितृसत्तात्मक सोच नहीं बदली।
न सिफ बदली नहीं, कभी-कभी
यह सोच ज्यादा कट्टू और
भयानक हुई क्योंकि स्त्रियों में
संघर्षशीलता बढ़ने के साथ
मर्दवादी सोच को घबराहट हुई
और उसने अपने शिकंजे का
ज्यादा पैना करने की कोशिश
की। आखिर स्त्री क्यों लपेट ली
जाती है कि किसी भी लड़ाई में?
शायद इसलिए कि वह प्रतिद्वंद्वियों
का सबसे नाजुक बिंदु है और हर
लड़ाई में हम अपने दुश्मन की
सबसे नाजुक कड़ी पर हमला
करना चाहते हैं। लेकिन स्त्री
इतनी नाजुक कड़ी क्यों बना दी
जाती है? शायद इसलिए कि हम
लगातार स्त्री के लिए ही कहते हैं
कि वह हमारे घर
(समाज/कौप) की इज्जत है,
सम्मान है। हम ऐसा कहते हैं,
चाहे अपने घर और कौप में उसे
अधिकारों से पूरी तरह वंचित
रखें और उसके समान पर
हमला भी करते रहें। स्त्री को घर

या बिरादरा का सम्मान मान समय आमतौर पर जो सुमिलता है, वह हमारे दोहरेपन देखता है। एक तो यह कि उस पुरुष को घर या बिरादरी इंजित बिल्कुल भी उस अर्थ नहीं मानते जिस अर्थ में स्त्री मानते हैं। स्त्रियों पर पुरुषों निजत्व के दावे के कारण किसी भी दृढ़ में सबसे नाजुक़ बड़ी बन जाती हैं और हमला का पहला निशाना बनती है। अगर पुरुष और स्त्रियां दोनों समान रूप से घर की इंजित मान जाएं, तो शायद स्त्रियों की ऐसी तरह की निशानदेही की एक वजह दूर हो जाए। लेकिन इसके सबसे बड़ा कारण तो वर्चस्ववादी प्रवृत्ति है, जिसे बचपन से पुरुषत्व के नाम से प्रोत्साहित करते हैं और जो स्त्रियों को बढ़ते कदमों से आज बहार आतंकित है। यह पुरुषों को संवेदना और सहयोग की क्षमता को तिल-तिल मारता है और उनके शरीर पर पुरुष की ताकत सेलिब्रेट करता है, पुरुष की ब

नत न-ख्व को हम की में को के वे तुक वर हैं। इनमों गाने इस एक का वह हम पर के हुत त्व बता त्री को बर्बर सबदनहान ताकत पर ताला बजाता है। ऐसी सोच में पोषित मर्द के लिए स्त्री देह को कब्जे में करना और उसके ऊपर मर्दनगी के झांडे गाड़ना ही उसके ह्याअसली मर्दहूँ होने का प्रमाण है। इस पुरुषकेंद्रित युद्ध को समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि मर्दवाद को मजबूत करने में सिर्फ पुरुषों का हाथ नहीं है। पिरुसत्ता या मर्दवाद एक सोच है, जो स्त्री और पुरुष को एकदम अलग तरह के इंसानों में विभाजित रखता है। इस विभाजित इंसानियत की सोच के पक्ष में सिर्फ पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी रही हैं। क्योंकि पुरुष और महिला दोनों में ये विचार बचपन से ही कूट-कूट कर भर दिए जाते हैं कि आत्म-सम्मान विहीन, साहस-विहीन और हर समय त्याग करने वाली स्त्री ही असल स्त्री होती है और जोर-जबरदस्ती करने वाला, दूसरों को दबा कर रखने वाला और अपनी इच्छा जबरन पूरी करने वाला पुरुष ही असल पुरुष होता है।

दुनिया में कैसे जग सकती है लपये की धाक

सच के हक में...

आप में से जो लोग शोध में रुचि रखते हैं, उन्हें उच्चतर शोध पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

मरीज के लिए दगा प्रीसक्राइब करना जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण नई औषधियां

विकसित करना हैं। मुझे उम्मीद है कि यदि आप

शोध जारी रखेंगे तो आप विकित्सा विज्ञान में नई दिशाओं की खोज कर पाएंगे। आप नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त कर सकते हैं।

(राष्ट्रपति द्वौपदी मुर्मू के टिवटर अकाउंट से)

कारगिल विजय दिवस भारत के उन अद्भुत

पाराक्रमियों की शौर्यगाथा को सामने लाता है, जो देशवासियों के लिए सदैव प्रेरणाशक्ति बने रहेंगे।

इस विशेष दिवस पर मैं उनका हृदय से नमन और वंदन करता हूं। जय हिंद!

(प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के टिवटर अकाउंट से)

अदम्य साहस, शौर्य और वीरता के प्रतीक

कारगिल विजय दिवस के अवसर पर देश के

अमर वीर जवानों की शहादत को शत-शत नमन।

(राष्ट्रपति नोबेल के विकास अकाउंट से)

1950 के दशक में, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, बहरीन, ओमान और कतर में लगभग सभी लेन-देन के लिए भारतीय रुपया वैध मुद्राएँ थीं। खाड़ी राजतंत्र पाउंड स्टर्लिंग के साथ रुपये खरीदते थे। 1959 में सोने की तस्करी से जुड़ी चुनौतियों को कम करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (संशोधन) अधिनियम लाया गया। इससे गल्फ रुपया अस्तित्व में आया। इसके तहत आरबीआई द्वारा केवल खाड़ी क्षेत्र के लिए नोट जारी किए गए थे। हालांकि 1966 आते-आते भारत ने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन कर दिया, जिससे डॉलर की विनिमय दर 4.76 रुपये से बढ़कर 7.5 रुपये हो गई। इसके कुछ महीने के भीतर कठर और यूरोप जैसे देशों ने खाड़ी रुपये को वापस ले लिया और इसे अपनी मुद्राओं से बदल दिया। दो हजार रुपये के नोटों को लेकर उठाए गए हालिया कदम ने विनिमय के माध्यम के रूप में रुपये के प्रति जताए जाने वाले भरोसे को प्रभावित किया है। इस दौरान खाड़ी

प्रभावित हुए हैं क्योंकि मुद्रा विनियम काउंटरोंने भारतीय रुपये के साथ लेन-देन करने से इनकार कर दिया है। रुपये को लेकर आम धारणा बदल गई है। यहां तक कि 500 रुपये के नोटों को भी कई बार अस्वीकृत झेलनी पड़ी है। हाल में ही विमुद्रीकरण ने भारतीय रुपये में विश्वास को हिला दिया। खासकर भूटान और नेपाल के नागरिकों पर इसका असर पड़ा। इस दौरान नेपाल ने अप्रैल 2018 तक के करीब 950 करोड़ रुपये के अमान्य भारतीय नोट समाप्त कर दिए। भूटान की रायल मॉनिटरी अथर्टिटी लगातार अपने नागरिकों को भारतीय मुद्रा रखने के जोखिमों के बारे में चेतावनी देती रहती है। दोनों देशों को फैक्ट द्वारा अतिरिक्त नीतिगत बदलावों का डर बना हुआ है। पड़ोसी देशों की चिंताओं पर गैर किए बिना रुपये का अंतरराष्ट्रीयकरण शुरू नहीं हो सकता। फिलहाल भारतीय रुपया अंतरराष्ट्रीयकरण से बहुत दूर है। वैश्विक विदेशी मद्रा बाजार में 1.6 फीसदी और ग्लोबल गुदम ट्रेड में भारत की हिस्सेदारी 2 फीसदी है। रुपये में व्यापार करने के लिए रूस के साथ चल रही बातचीत की गति खासी सुस्त है। रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि रूसी बैंक मुद्रा के और अधिक अवमूल्यन के जोखिम और स्थानीय मुद्रा सुविधाओं के बारे में व्यापारियों के बीच जागरूकता की कमी को देखते हुए व्यापार के प्रति अनिच्छुक बने हुए हैं। सीधे शब्दों में कहें तो भारतीय रुपये में व्यापार करने की मांग बहुत कम है। हमें युआन का अंतरराष्ट्रीयकरण करने के चीन के उदाहरण से सीखना चाहिए। 2007 तक चीन ने युआन बॉन्ड का बाजार बनाया। खासतौर पर हॉन्गकांग में वित्तीय संस्थानों को 2009 तक ऐसे बॉन्ड जारी करने की इजाजत दी गई, जिन्हें युआन में भुनाया जाना था। 2008 के बाद चीन ने व्यापार और वाणिज्य के लिए वित्तीय साधन के साथ निवेश और लंबी अवधि में आरक्षित मद्रा के रूप में युआन के



BRIEF NEWS

फुटबॉल खिलाड़ियों से सामाजिक कार्यकर्ता मिले, मदद का दिया आश्वासन



ROURKELA : रघुनाथपल्ली विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सेक्टर 7/17 स्थित अंडेकटर मैदान में आयोजित किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में उपायुक्त अनन्य मितल एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला शिक्षा पदाधिकारी अध्यक्ष कुमार शील ने मुकामात की हानि सभी फुटबॉल खिलाड़ियों से विभिन्न सुविधाओं और प्राचार्य के बारे में विद्यालय के निदेशक और प्राचार्य का तिलक लगाकर बैंडग्रुप के द्वारा स्कॉट कर कार्यक्रम स्थल तक लाया गया। इसके बाद अतिथियों ने विद्यालय के सीनियर ब्लॉक का उद्घाटन किया। तत्पश्चात विद्यालय के नाम रोशन करने का आहान किया। इस दौरानमें पूर्व क्रिकेटर व रणजी खिलाड़ी साक्षी हुसैन, कैलाश चंद्र साह, भगवान सेठी, बैंडेंट टेट, देवदी राव, मनोज साहु प्रमुख रूप से उपस्थित थे।

बड़मुंदा से माओवादी के नाम पर ठगी करने का आरोपी गिरफ्तार



ROURKELA : बड़मुंदा इताके में माओवादी के नाम पर पैसे मांगने के अरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है गिरफ्तार व्यक्ति मध्यसून दास के पास से 50 हजार रुपये नकद, 2 लोड बिल फोन और एक स्कूटी जब किया गया है। बड़मुंदा डॉ सेक्टर में पूर्ण वाले मध्यसून ने माओवादियों के नाम का इतामाल कर एक स्थानीय दवा दुकान से 6 लाख रुपये की मांग की। दुकानदार ने पैसे देने में असमर्थता जताई। अंत में वे छेड़ लाख रुपये देने पर राजी हो गए।

दूसरी दवा की फहली किस्त लेते समय बड़मुंदा और विसरा पुलिस ने मध्यसून को गिरफ्तार कर कोर्ट चालान कर दिया गया है।

घर में आग लगने से लाखों की संपत्ति खाक



SUNDARGARH : जिले के लहुणीपाड़ा थाना अंतर्गत खंटांगांव गांव में एक घर में आग लगने से लाखों रुपये की क्षति जल गई। माना जा रहा है कि आग शैर्ट सर्किट के घर में बीती रात अचानक आग लग गयी। आग फैलने से घर में धुआं भर गया और फैलने वाले जल गया।

इस अवसर पर विद्यालय की प्रार्थना सभा में उपस्थित करीब 1000 बच्चों को कार्यगिल में शहीद हुए भारत के सपूतों को भारत देश का सच्चा वीर बताया गया। सच्चा वीर शिक्षक अनंत कुमार उपाध्याय की अध्यक्षता में स्कूली शिक्षकों के द्वारा कार्यगिल के वीर शहीदों को नमन करते हुए पुष्प अर्पित किया गया।

इस अवसर पर विद्यालय की अध्यक्षता में अंतर्गत राज्यव्यायाम योग्य और प्रशिक्षियों को बुलाया गया। व्यायाम के दौरान विद्यालय के बारे में बातें जारी की गयी। इसमें संबोधन में कहा गया कि 26 जुलाई 1999 को भारतीय सेना ने अपने संबोधन में कहा कि 26

जुलाई 1999 को भारतीय सेना ने अपने संबोधन में कहा कि 26

जुलाई 1999 को भारतीय सेना ने अपने संबोधन में कहा कि 26

जुलाई 1999 को भारतीय सेना ने अपने संबोधन में कहा कि 26

जुलाई 1999 को भारतीय सेना ने अपने संबोधन में कहा कि 26

जुलाई 1999 को भारतीय सेना ने अपने संबोधन में कहा कि 26

जुलाई 1999 को भारतीय सेना ने अपने संबोधन में कहा कि 26

जुलाई 1999 को भारतीय सेना ने अपने संबोधन में कहा कि 26

जुलाई 1999 को भारतीय सेना ने अपने संबोधन में कहा कि 26

जुलाई 1999 को भारतीय सेना ने अपने संबोधन में कहा कि 26

जुलाई 1999 को भारतीय सेना ने अपने संबोधन में कहा कि 26

जुलाई 1999 को भारतीय सेना ने अपने संबोधन में कहा कि 26

जुलाई 1999 को भारतीय सेना ने अपने संबोधन में कहा कि 26

जुलाई 1999 को भारतीय सेना ने अपने संबोधन में कहा कि 26

जुलाई 1999 को भारतीय सेना ने अपने संबोधन में कहा कि 26

जुलाई 1999 को भारतीय सेना ने अपने संबोधन में कहा कि 26

जुलाई 1999 को भारतीय सेना ने अपने संबोधन में कहा कि 26

जुलाई 1999 को भारतीय सेना ने अपने संबोधन में कहा कि 26

जुलाई 1999 को भारतीय सेना ने अपने संबोधन में कहा कि 26

जुलाई 1999 को भारतीय सेना ने अपने संबोधन में कहा कि 26

जुलाई 1999 को भारतीय सेना ने अपने संबोधन में कहा कि 26

जुलाई 1999 को भारतीय सेना ने अपने संबोधन में कहा कि 26

जुलाई 1999 को भारतीय सेना ने अपने संबोधन में कहा कि 26

जुलाई 1999 को भारतीय सेना ने अपने संबोधन में कहा कि 26

जुलाई 1999 को भारतीय सेना ने अपने संबोधन में कहा कि 26

जुलाई 1999 को भारतीय सेना ने अपने संबोधन में कहा कि 26

जुलाई 1999 को भारतीय सेना ने अपने संबोधन में कहा कि 26

जुलाई 1999 को भारतीय सेना ने अपने संबोधन में कहा कि 26

जुलाई 1999 को भारतीय सेना ने अपने संबोधन में कहा कि 26

जुलाई 1999 को भारतीय सेना ने अपने संबोधन में कहा कि 26

जुलाई 1999 को भारतीय सेना ने अपने संबोधन में कहा कि 26

जुलाई 1999 को भारतीय सेना ने अपने संबोधन में कहा कि 26

जुलाई 1999 को भारतीय सेना ने अपने संबोधन में कहा कि 26

जुलाई 1999 को भारतीय सेना ने अपने संबोधन में कहा कि 26

जुलाई 1999 को भारतीय सेना ने अपने संबोधन में कहा कि 26

जुलाई 1999 को भारतीय सेना ने अपने संबोधन में कहा कि 26

जुलाई 1999 को भारतीय सेना ने अपने संबोधन में कहा कि 26

जुलाई 1999 को भारतीय सेना ने अपने संबोधन में कहा कि 26

जुलाई 1999 को भारतीय सेना ने अपने संबोधन में कहा कि 26

जुलाई 1999 को भारतीय सेना ने अपने संबोधन में कहा कि 26

जुलाई 1999 को भारतीय सेना ने अपने संबोधन में कहा कि 26

जुलाई 1999 को भारतीय सेना ने अपने संबोधन में कहा कि 26

जुलाई 1999 को भारतीय सेना ने अपने संबोधन में कहा कि 26

जुलाई 1999 को भारतीय सेना ने अपने संबोधन में कहा कि 26

जुलाई 1999 को भारतीय सेना ने अपने संबोधन में कहा कि 26

जुलाई 1999 को भारतीय सेना ने अपने संबोधन में कहा कि 26

जुलाई 1999 को भारतीय सेना ने अपने संबोधन में कहा कि 26

जुलाई 1999 को भारतीय सेना ने अपने संबोधन में कहा कि 26

जुलाई 1999 को भारतीय सेना ने अपने संबोधन में कहा कि 26

जुलाई 1999 को भारतीय सेना ने अपने संबोधन में कहा कि 26

जुलाई 1999 को भारतीय सेना ने अपने संबोधन में कहा कि 26

जुलाई 1999 को भारतीय सेना ने अपने संबोधन में कहा कि 26

जुलाई 1999 को भारतीय सेना ने अपने संबोधन में कहा कि 26

जुलाई 1999 को भारतीय सेना ने अपने संबोधन में कहा कि 26

जुलाई 1999 को भारतीय सेना ने अपने संबोधन में कहा कि 26

जुलाई 1999 को भारतीय सेना ने अपने संबोधन में कहा कि 26

जुलाई 1999 को भारतीय सेना ने अपने संबोधन में कहा कि 26

जुलाई 1999 को भारतीय सेना ने अपने संबोधन में कहा कि 26

जुलाई 1999 को भारतीय सेना ने अपने संबोधन में कहा कि 26

जुलाई 1999 को भारतीय सेना ने अपने संबोधन में कहा कि 26

जुलाई 1999 को भारतीय सेना ने अपने संबोधन में कहा कि 26

जुलाई 1999 को भारतीय सेना ने अपने संबोधन में कहा कि 26

जुलाई 1999 को भारतीय सेना ने अपने संबोधन में कहा कि 26

